

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

मा० मुख्यमंत्री संदर्भ

अपर परियोजना निदेशक
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव
शिक्षा अनुभाग-5
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक: गुण०वि० / मुख्यमंत्री लम्बित संदर्भ / 2541 / 2014-15 दि० // सितम्बर, 2014

विषय: पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक बी०आर०सी० / यू०आर०सी० केन्द्रों पर नये सिरे से सह-समन्वयकों के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, उ०प्र० के लम्बित प्रकरणों की सूची दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के कम्प्यूटर संदर्भ संख्या-PG10476410 दिनांक 10 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न श्री जय प्रकाश अंचल, मा० सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य, प्राक्कलन समिति, विधान सभा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा माँग की गयी है कि वर्तमान समय में कार्यरत ब्लाक संसाधन केन्द्र सह-समन्वयकों का चयन पूर्व सरकार के समय किया गया था। अतः इन सह-समन्वयकों का नवीनीकरण न किया जाये तथा नवीन चयन हेतु शासनादेश जारी किया जाये।


सूच्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों को प्रभावी रूप से शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर संसाधन केन्द्र स्थापित हैं। "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के परिप्रेक्ष्य में इन संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था को शासनादेश संख्या-3903/79-5-2010-424/02टी.सी. दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित व्यवस्था में यह प्राविधान है कि "विकासखण्ड संसाधन केन्द्र के सह-समन्वयकों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा और कार्य संतोषजनक होने पर 03 वर्ष के कार्यकाल की अवधि जिलाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त ही बढ़ाई जा सकेगी। 06 वर्ष की सेवा के उपरान्त पुनः नवीन चयन किया जायेगा।"

0/4

सम्प्रति ब्लाक संसाधन केन्द्र सह-समन्वयकों के नवीनीकरण की कार्यवाही शासनादेश संख्या-3903/79-5-2010- 424/02टी.सी. दिनांक 02 फरवरी, 2011 के अनुपालन में की जा रही है तथा इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। ऐसी दशा में वर्तमान समय में कार्यरत सह-समन्वयकों का नवीनीकरण रोकना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीया,


डॉ०(शुभ्र ज्योत्सना त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक